भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2075

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरों में शौचालय की सुविधा

2075. श्री रवि किशनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में जिन घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कुल संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में शौचालय के निर्माण हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या अधिकतर शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त शौचालयों को उपयोग योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शौचालय वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या तथा प्रतिशत **अनुलग्नक** में दिए गए है।

(ख) वर्ष 2017-18 से पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त की जा चुकी हैं। तथापि, पिछले चार वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आबंटित निधियां इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)
1.	2014-15	2850.00
2.	2015-16	6525.00
3.	2016-17	10513.00
4.	2017-18	16948.27
5.	2018-19*	14478.10*
6.	2019-20 (अंतरिम बजट)	10000.00

*इसके अलावा वर्ष 2018-19 के दौरान अतिरिक्त बजटीय संसधानों के माध्यम से 8698.20 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाई गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018-19 के परिणामों के अनुसार 96.5 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा है और वह इनका उपयोग करते है।

(ड.) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, हाथ धोने और सफाई हेतु जल भंडारण सहित जल उपलब्ध कराने हेतु वैयक्तिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में स्वच्छता और जल के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन का तालमेल करने और स्वच्छता के प्रयोजन हेतु जल की उपलब्धता को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पैन का भी उपयोग किया जाता है। जिसमें फ्लशिंग के लिए केवल 1-2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

अनुलग्नक

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

दिनांक 28.06.2019 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ऑनलाइन आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शौचालय वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या और प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय वाले परिवारों की संख्या	शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37359	100.00
2	आंध्र प्रदेश	7240118	100.00
3	अरुणाचल प्रदेश	200018	100.00
4	असम	5281314	100.00
5	बिहार	15537021	100.00
6	चंडीगढ़	25454	100.00
7	छत्तीसगढ़	4845141	100.00
8	दादरा व नगर हवेली	33324	100.00
9	दमन व दीव	1725	100.00
10	गोवा	139713	89.15
11	गुजरात	5215314	100.00
12	हरियाणा	2705487	100.00
13	हिमाचल प्रदेश	1433783	100.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	1504335	100.00
15	झारखंड	4081595	100.00
16	कर्नाटक	7080914	100.00
17	केरल	4682729	100.00
18	लक्षद्वीप	10850	100.00
19	मध्य प्रदेश	9234184	100.00
20	महाराष्ट्र	11356239	100.00
21	मणिपुर	450717	100.00
22	मेघालय	443083	100.00
23	मिजोरम	124012	100.00
24	नागालैंड	256152	100.00
25	ओडिशा	6844057	86.71
26	पुडुचेरी	88163	100.00
27	पंजाब	2854501	100.00
28	राजस्थान	10573228	100.00
29	सिक्किम	57499	100.00
30	तमिलनाडु	9832234	100.00
31	तेलंगाना	4171018	98.36
32	त्रिपुरा	631596	100.00
33	उत्तर प्रदेश	26821782	100.00
34	उत्तराखंड	1540968	100.00
35	पश्चिम बंगाल	13533229	100.00
	कुल	**15,88,68,856**	**99.29**